



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)  
प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 196] नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 31, 1993/बैत 10, 1915

No. 196] NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 31, 1993/CHAITRA 10, 1915

इस भाग में विभिन्न पट्ट संख्या दी जाती हैं जिससे कि यह अलग सफ इन के रूप में  
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be field as a  
separate compilation

उद्योग मन्त्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

मुद्रण

नई दिल्ली, 31 मार्च, 1993

का ग्रा 218(प्र) /18क/ग्राउड डा प्रा.ग.प. /9.3--मार्ग सरकार के उद्योग मन्त्रालय  
(औद्योगिक विकास विभाग) के कानून अ. इंग. 52। 157(प्र) 18क/ग्राउड डा प्रा.ग.प. /  
79, त.राव्र 27 मार्च, 1979 द्वारा (जि. इसमें उसके पश्चात् उत्तर देश कहा गया है)

कलकत्ता में स्थित मैसर्स विल्ली ब्रिस्कुट कंपनी (ब्राइवेट) निमिटेड और मैसर्स विल्ली बालै मिल्स (प्राइवेट) लिमिटेड नामक दोनों औद्योगिक उपकरण के प्रबंध का 27 मार्च, 1979 से तीन वर्ष की अवधि के लिये अधिग्रहण किया गया था और रुग्ण और बन्द उद्योग विभाग, जो अब औद्योगिक पुनर्निर्माण विभाग, कलकत्ता के नाम से जाना जाता है, में पश्चिम बंगाल सरकार के सचिव को 'प्राधिकृत नियंत्रक' के रूप में नियुक्त किया गया था,

और यह केन्द्रीय सरकार ने अपनी यह राय होते पर कि लोकहित में यह समीनीत है कि उक्त आदेश पूर्वोक्त तीन वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्रभावी बना रहे 31 मार्च, 1993 तक की और अवधि के लिये ऐसे बने रहने के लिये समय-समय पर निर्देश जारी किये थे। देखिए भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश-

- म. का.आ. 178(अ)/18क/प्राई.डी.आर.ए./82, नारोब 26 मार्च, 1982
- म.का.आ. 688(अ)/18क/प्राई.डी.आर.ए./82 नारोब 25 मिस्रावर, 1982
- म. का.आ. 384(अ)/18क/प्राई.डी.आर.ए./83, नारोब 31 मई, 1983
- म.का.आ. 936(अ)/19क/प्राई.डी.आर.ए./83, नारोब 29 दिसंबर, 1983
- म.का.आ. 469(अ)/18क/प्राई.डी.आर.ए./84, नारोब 28 जून, 1984
- म.का.आ. 967(अ)/18क/प्राई.डी.आर.ए./84, नारोब 28 दिसंबर, 1984
- म.का.आ. 280(अ)/18क/प्राई.डी.आर.ए./85, नारोब 30 मार्च, 1985
- म. का.आ. 144(अ)/18क/प्राई.डी.आर.ए./86, नारोब 31 मार्च, 1986
- म.का.आ. 271(अ)/18क/प्राई.डी.आर.ए./87, नारोब 30 मार्च, 1987
- म.का.आ. 327(अ)/18क/प्राई.डी.आर.ए./88, नारोब 30 मार्च, 1988
- म.का.आ. 246(अ)/18क/प्राई.डी.आर.ए./89, नारोब 31 मार्च, 1989
- म.का.आ. 275(अ)/18क/प्राई.डी.आर.ए./90, नारोब 30 मार्च, 1990
- म.का.आ. 213(अ)/18क/प्राई.डी.आर.ए./91, नारोब 26 मार्च, 1991 और
- म.का.आ. 249(अ)/18क/प्राई.डी.आर.ए./92, नारोब 30 मार्च, 1992

और यह केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि लोकहित में यह समीनीत है कि उक्त आदेश 31 मार्च, 1994 तक की, जिसमें यह नारोब भी सम्मिलित है, और अवधि के लिये प्रभावी बना रहे,

ग्रत., श्रव., केंद्रीय सरकार, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) का धारा 18क के उपशारा (2) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह निवेश देता है कि 27 मार्च, 1979 का उक्त आवेदन 31 मार्च, 1994 तक का, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, और अवधि के लिये प्रभावी बन रहेगा।

[फा.स. 2(3)/80 सी.यू.एस./प्राई.आर.एस.]

ग्रबण्ड प्रताप सिंह, मयुक्त सचिव

MINISTRY OF INDUSTRY  
(Department of Industrial Development)  
ORDER

New Delhi, the 31st March, 1993

S.O. 218(E)|18A|IDRA|93.—Whereas by the Order of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) No. S.O. 157(E)|18A|IDRA 79 dated the 27th March, 1979 (hereinafter referred to as the said Order) the management of industrial undertakings known as Messrs. Lily Biscuit Company (Private) Limited and Messrs Lily Barley Mills (Private) Limited, both located at Calcutta, had been taken over for a period of three years with effect from the 27th March, 1979 and the Secretary to the Government of West Bengal in the Department of Sick and Closed Industries now known as Department of Industrial Reconstruction, Calcutta, was appointed as 'Authorised Controller'.

And, whereas, the Central Government being of opinion that it is expedient in the public interest that the said order should continue to have effect after the expiry of the period of three years aforesaid, had issued directions from time to time, for such continuance for a further period upto 31st March, 1993 (vide Orders of the Government of India in the Ministry of Industry, Department of Industrial Development).

Nos S.O. 178(E)|18A|IDRA|82, dated the 26th March, 1982,

S.O. 638(E)|18A|IDRA|82, dated the 25th September, 1982,

S.O. 384(E)|18A|IDRA|83, dated the 31st May, 1983,

S.O. 936(E)|18A|IDRA|83, dated the 29th December, 1983,

S.O. 469(E)|18A|IDRA|84, dated the 28th June, 1984,

S.O. 967(E)|18A|IDRA|84, dated the 28th December, 1984,

S.O. 280(E)|18A|IDRA|85, dated the 30th March, 1985,

- S.O. 144(E) 18A IDRA 86, dated the 31st March, 1986,  
S.O. 271(E) 18A IDRA 87, dated the 30th March, 1987,  
S.O. 327(E) 18A IDRA 88, dated the 30th March, 1988,  
S.O. 246(E) 18A IDRA 89, dated the 31st March, 1989,  
S.O. 275(E) 18A IDRA 90, dated the 30th March, 1990,  
S.O. 213(E) 18A IDRA 91, dated the 26th March, 1991 and  
S.O. 249(E) 18A IDRA 92, dated the 30th March, 1992.

And whereas, the Central Government is of the opinion that it is expedient in the public interest that the said order should continue to have effect for a further period upto and inclusive of 31st March, 1994.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the proviso to subsection (2) of Section 18A of the Industries (Development & Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby directs that the said Order dated the 27th March, 1979 shall continue to have effect for a further period upto and inclusive of the 31st March, 1994.

[File No. 2(3), 80-CUS (RS)]

A. P. SINGH Jt. Secy.